संकल्प पत्र

दिल्ली विधानसभा 2020

भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश

दिल्ली में साफ़, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त सरकार देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए हम सभी जरूरी कदम उठाएंगे।

2022 तक सबको आवास और मालिकाना हक़

- दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख निवासियों को मालिकाना हक़ देने के बाद, उन्हें रजिस्ट्री देने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इन कॉलोनियों के समुचित विकास के लिए एक समर्पित "कॉलोनीज़ डेवलपमेंट बोर्ड" का गठन किया जाएगा।
- दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया जाएगा जिसके तहत दिल्ली में 2022 तक सभी को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
- सेल्फ अलॉटमेंट सोसाइटियों के एनओसी के प्रश्न को हल करने के लिए तेज गति से कदम उठाये जाएंगे।
- पगड़ी किरायदारों के न्यायोचित हितों की सुरक्षा करने के लिए हम सभी जरूरी कदम उठाएंगे।

व्यापार और उद्योग

- 10 लाख व्यापारियों के दुकानों-दफ्तरों को लीज्होल्ड से फ्रीहोल्ड कराने का कार्य युद्ध-स्तर पर किया जाएगा।
- 3 लाख घरेलु उद्योगों के कामकाज के लिए आवश्यक अनुमतियों को सरल बनाकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अब इन्हें कामकाज में कोई मुश्किल न आये।
- सीलिंग के कारण परेशान व्यापारी और कारोबारियों को राहत देने के लिए हम सभी प्रशासनिक और कानूनी कदम उठाएंगे। रेड़ी-पटरी वालों को नियमित करने के लिए तुरंत सर्वे किया जाएगा और उनको जीवन बीमा भी दिया जाएगा।

सामाजिक सेवाएं

- 5 लाख रुपये के मुफ्त इलाज का लाभ देने वाली प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू किया जाएगा।
- दिल्ली के छात्रों को आधुनिकतम शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा और स्वस्थ्य के बजट में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
- दिल्ली में 10 नए कॉलेज और 200 नए स्कूल शुरू किये जायेंगे।

ईज ऑफ़ लिविंग

- दिल्ली को पूरी तरह टैंकर मुक्त करने के लिए हम संकल्पित हैं। वर्ष 2024 तक हर घर नल से स्वच्छ पेयजल प्राथमिकता से उपलब्ध कराया जायेगा।
- हम 10 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ एक नयी "समृद्ध दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर योजना" की शुरुआत करेंगे जिसके माध्यम से दिल्ली में बेहतर सड़क, फ्लाइओवर आदि बुनियादी ढाँचे का निर्माण प्राथमिकता और लक्षित रूप से किया जाएगा।
- हम दिल्लीवासियों को कचरे के ढेरों से पूरी तरह से मुक्ति दिलाएंगे।

महिलाओं का सम्मान

- आर्थिक रूप से कमजोर प्रत्येक परिवार की पहली 2 लड़कियों के जन्म के साथ उनके नाम से निश्चित राशि सरकार द्वारा खाते में जमा की जाएगी और उनके 21 साल के होने पर उन्हें 2 लाख रुपयों का लाभ मिलेगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ रहीं लड़कियों को हम निशुल्क साइकिल देंगे।
- 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के अंतर्गत कॉलेज में प्रवेश लेने वाली आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की छात्राओं को हम निशुल्क इलेक्ट्रिक स्कूटी देंगे।
- महिलाओं के उत्थान और समुचित विकास की योजनाओं पर विमर्श करने और सुझाव देने हेतु हम एक विशेष 'महिला सशक्तिकरण मिशन बोर्ड' की स्थापना करेंगे।
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यापक कदम उठाने और उसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने हेतु 'रानी लक्ष्मीबाई महिला सुरक्षा योजना' की शुरुआत की जाएगी।
- गरीब विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह पर सरकार 51 हजार रुपए का विशेष उपहार देगी।

युवा ऊर्जा का विकास - कौशल-विकास एवं रोजगार

- हम अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में कम से कम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे।
- युवाओं सर्वांगीण विकास के लिए हम एक समर्पित 'युवा कल्याण बोर्ड' का गठन करेंगे।

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास

- 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर गेंहूँ का आटा गरीब परिवारों को मिलेगा।
- सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के विकास के लिए 'आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग' का गठन किया जाएगा।
- अति पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए हम एक अलग 'अति पिछड़ा वर्ग बॉर्ड' का गठन करेंगे।
- यमुना की स्वच्छ और निर्मल धारा को सुनिश्चित करने और उसके आस-पास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए दिल्ली यमुना विकास बोर्ड का गठन किया जायेगा। यमुना नदी के धार्मिक महत्व को अधिक उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर 'यमुना महोत्सव' मनाया जाएगा।
- दिल्ली के अस्पतालों, सरकारी स्कूलों और अन्य सभी सरकारी निकायों एवं संस्थानों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों को 58 वर्ष तक कार्य करते रहने की जॉब गारंटी मिलेगी।
- दिल्ली के किसानों को 6000 रुपये की सम्मान निधि सीधे उनके खाते में दिया जाएगी।

देश बदला
अब दिल्ली बदलो

कमल का बटन दबाएं भाजपा को जिताएं